Newspaper Clips

September 13-14, 2016

September 14

QS World University Rankings: Indian Universities in Top 50

http://www.enaindia.in/news/newsdetails/grade/higher-education/qs-world-university-rankings-indian-universities-in-top-50

QS World University Rankings: Indian Universities in Top 50

New Delhi September 14 (ENA) Quacquarelli Symonds (QS), a higher education think tank has prepared a list of the world's best universities, the QS World University Rankings 2016. This year 4 Indian Institutes of Technology, Mumbai, Delhi, Madras and Kanpur, and Indian Institute of Science has made it to top 50

The IISc, has maintained it top position among the the Indian Institute. It is at 33rd this year. Other Universities such as the IIT-Mumbai ranks 35th, followed by the IIT-Delhi (36th), IIT-Madras (43rd) and IIT-Kanpur (48th), the IIT-Kharagpur at 51 ranking and two other IITs, Roorkee at 78 and Guwahati at 94 made it to the top 100. Some central universities have made some progress well compared to last year. The University of Delhi last year ranked 91st position has this year jumped to 66th place. The University of Calcutta last year was at 149th position, this year it jumped to 108th position. The University of Mumbai holds 145th place while Banaras Hindu University is placed at 155th position. Panjab University is in the 251 to 300 bracket. Institute of Science, Bangalore (IISC) have made it to the top 50 in the rankings.

Out of the list of 350 universities, India has 23 universities in the list.

Amar Ujala ND 14.09.2016 P-06

जैब फाइनल करेगी देशभर में आईआईटी की प्रवेश प्रक्रिया

सत्र 2017-18 के लिए पहली मीटिंग 18 को बुलाई गई

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर।

देश की 22 आईआईटी में एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया 18 सितंबर को फाइनल हो जाएगी। इसी सिलसिले में ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड (जैब) की पहली मीटिंग आईआईटी मद्रास में बुलाई गई है। जैब ही ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) एडवांस 2017 की पूरी प्रक्रिया तय करेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रवेश परीक्षा, रिजल्ट जारी करने और एडमिशन का विस्तृत शेड्यूल भी जारी होगा।

जेईई एडवांस 2017 का आयोजन आईआईटी मद्रास की

देखरेख में होगा। इसके चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। इस बार जेईई एडवांस का परिक्षेत्र बढ़ाया जाना है। अभी सात आईआईटी परिक्षेत्र (कानपुर, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर और मद्रास) की देखरेख में प्रवेश परीक्षा होती थी। अब देश में 22 प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। जैब से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सत्र 2017-18 से विदेशी स्टूडेंटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

इसके लिए श्रीलंका, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात सहित नौ देशों के स्टूडेंटों को सीधे जेईई एडवांस का पेपर देने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर सहमति बन चुकी है। अंतिम मुहर जैब को लगानी है।

विदेशी स्टूडेंटों को अभी तक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) मेन का पेपर देना पड़ता है। इसे क्वालीफाई करने के बाद एडवांस का पेपर देने को मिलता है। अब इस अनिवार्यता से छूट देने की तैयारी है।

Amar Ujala ND 14.09.2016 P-11

अब आईआईटी देंगे एमआईटी को टक्कर

रैंकिंग सुधारने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात दुरुस्त करने का फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में शामिल होने के लिए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे दुनिया के शीर्ष शिक्षण संस्थानों को टक्कर देगा। आईआईटी काउंसिल ने इसकी रैंकिंग सुधारने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। अब पांच पीएचडी छात्र एक फैकल्टी माने जाएंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, आईआईटी काउंसिल की बैठक में देसी संस्थान के दुनिया के सौ सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में शामिल न होने पर भी चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि रैंकिंग सुधारने में सबसे पहले छात्र-शिक्षक अनुपात को ठीक करना होगा। इस पर फैसला हुआ कि अब पांच पीएचडी स्कॉलर्स एक फैकल्टी के रूप में माने जाएंगे। क्योंकि आईआईटी में पीएचडी स्कॉलर्स भी अंडरग्रेजुएट छात्रों को पढ़ाते हैं। देशभर के आईआईटी में इस समय 26 हजार पीएचडी स्कॉलर्स हैं। जबकि आईआईटी में करीब 26 सौ फैकल्टी की जरूरत है।

10 छात्र पर अब एक फैकल्टी मिलेगी अंतरराष्ट्रीय मानक की होगी बराबरी

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में शामिल करने का खाका तैयार

भारत के शिक्षण संस्थान सर्वश्रेष्ठ सौ में भी शामिल नहीं

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016 ब्रिटेन में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के एमआईटी पहले और स्टैनफोर्ड व हार्वर्ड क्रमश: दूसरे तीसरे नंबर पर थे। जबकि आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 179 रैंक से खिसक कर 185 हो गई है। वहीं, टॉप 400 की सूची में आईआईटी मुंबई 219 नंबर, चेन्नई 249, आईआईटी कानपुर 302, आईआईटी खड़गपुर 313 और आईआईटी रुड़की की रैंकिंग 399 नंबर रही। इस सर्वेक्षण के बाद क्यूएस के शोध प्रमुख बेन सोवटर ने कहा था कि रैंकिंग की तुलना निवेश से की जा सकती है। इससे पता चलता है कि कौन सा देश प्रगति कर रहा है और कौन नहीं।

Navodaya Times ND 14.09.2016 P-07

आईआईटी एमटेक के छात्र बीच में छोड़ रहे पढ़ाई

- पीएसयू में नौकरी बन रही है पढ़ाई छोड़ने का कारण
- परिषद उठा सकती है कड़े कदम, वापस होगी फेलोशिप
- देश के आईआईटी में 14 हजार एमटेक रजिस्ट्रेशन है
- करीब 2 हजार विद्यार्थियों ने पूरी नहीं की अपनी डिग्री

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (शशिकांत वत्स): पीएसयू (पब्लिक स्टेट अंडरटेकिंग) कंपनियों में नौकरी लगने के चलते आईआईटी एमटेक के छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं जिससे सत्र के बीच में ही सीटें खाली हो रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई है। ऐसे छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर रोक लगाने के लिए आईआईटी परिषद प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत छात्रों से फेलोशिप की रकम वापस लेने जैसे कड़े कदम उठाने का फैसला भी ले सकती है। साथ ही पीएसयू छात्रों को इस बात के लिए आश्वस्त करेगी कि उनकी नौकरी किसी और को नहीं दी जाएगी और पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे नौकरी मिल जाएगी।

देश में 23 आईआईटी हैं जिनमें कुल 72 हजार छात्र पढ़ रहे हैं और इसमें 14 हजार छात्र एमटेक में पंजीकृत हैं। आईआईटी एमटेक के छात्र बीच में पढ़ाई छोड़कर पीएसयू में नौकरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हाल में आईआईटी परिषद की मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि करीब दो हजार छात्र बीच में ही एमटेक की पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आईआईटी देश के नामचीन संस्थानों में एक है। इसमें दाखिला लेने के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ने से सीट खाली रह जाती हैं। बताया जाता है कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों पर नौकरी को लेकर दबाव रहता है। एक प्रोफेसर ने बताया कि हम छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा हालात चिंताजनक है जिसके लिए शीघ्र ही मंत्रालय पीएसयू को भी लिखेगा।

आईआईटी एमटेक में दाखिले के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट (गेट) होता है, लेकिन पीएसयू में नौकरी मिलने से छात्रों को डर रहता है कि कहीं नौकरी हाथ से चली न जाए जिसके डर से छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ना मजबूरी बन जाती है। परिषद का मानना है कि ऐसे छात्रों को हतोत्साहित करने के लिए अगर पढ़ाई बीच में ही छोड़े तो उनकी 12400 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली फेलोशिप वापस ली जा सकती है, जिसके लिए आईआईटी परिषद इस पर विचार कर रही है। साथ ही पीएसयू भी छात्रों को यह आश्वस्त करेगी कि उनकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी वह पढ़ाई पूरी करके उनके यहां नौकरी पा सकते हैं।

Hindustan Times ND 14.09.2016 P-20

IIMs modify admission rules for non-engineers

While some Indian Institutes of Management (IIMs) altered intake policies to encourage more non-engineers to join a few years ago, IIMs such as Ahmedabad and Calcutta have announced recent changes for PGP 2017-19 batch.

While less weightage is proposed to be awarded to CAT 2016 scores, academic and gender diversity, academic profile, work experience, among other things, are likely to be given more weightage. This is aimed at not giving a particular section of test takers an advantage in the CAT.

The selection of the candidates for admission to the 2017-19 batch of the PGP at IIM-A is a two-step process. In the first step, candidates are short-listed for Academic Writing Test (AWT) and Personal Interview (PI) from among the candidates who have a valid CAT 2016 score, who have applied to the programme and who satisfy the eligibility criteria for the programme.

THE WEIGHTAGE ON CAT SCORE FOR THE FINAL SELECTION AT IIM-A IS 28% THIS YEAR, REDUCED FROM 2015 WHEN IT WAS 35%

The weightage on CAT score is 70% for shortlisting for interviews, which is unchanged from last year.

The weightage on CAT score for the final selection is 28% this year, reduced slightly from 2015 when it was 35%.

"To ensure diversity at IIM-A PGP, every year a certain number of top candidates from each of seven different academic categories (broadly medical, professional degrees CA/CS/ICWA, science, commerce, arts, engineering and others) are shortlisted for AWT and PI on the basis of their composite score 'CS' (computed based on CAT score and academic performance) subject to their fulfilling certain criteria," says a spokesperson from the IIM Ahmedabad admissions committee.

A certain number of candidates from each of the academic disciplines will be shortlisted for AWT and PI on the basis of their composite score, subject to the fulfilling of criteria. This figure may go up to 5% of the total candidates in one discipline, as compared to the top 1% earlier.

At IIM Calcutta, for the 2016-18 batch, the weightage for shortlisting for personal interview and written ability test was 67% for CAT score and 15% each for Class 10 and Class 12 scores. Women candidates also got 3% extra in a bid to boost gender diversity.

As per the new policy, the CAT score will be 28 (56%), Class 10 and Class 12 score will be 10 points each (20% each) and gender diversity 2 points (4%).

GAURI KOHLI

Hindustan Times ND 14.09.2016 P-20

Why IIMs want student diversity

MIX N MATCH

Encouraging students from other backgrounds, besides engineering, will help break homogeneity at Indian Institutes of Management, say experts

Gauri Kohli
gauri.kohli@hindustantimes.com

Engineers have dominated the classrooms at Indian Institutes of Management (IIMs) for several years. Now, the focus is shifting towards boosting academic and gender diversity by altering intake rules. According to officials at several IIMs, getting candidates from areas other than engineering is must for breaking the homogeneity on campus. They also say that since the pedagogy involves discussion-based methods, it is a strong reason to boost academic diversity as students with different perspectives will make learning more inclusive. Besides engineers, most candidates are from commerce, arts, medicine/dentistry, pharmacy/pharmacology etc.

NON-ENGINEERS ON THE RISE

Take IIM Ahmedabad, for instance. Non-engineering students in the PGP batch have gone up from 5% in 2011 to 20% this year. While there were 20 non-engineers in the 2011-13 batch, the 2016-18 batch comprises 80 non-engineers. At IIM Bangalore, the 2016-18 batch includes 11% non-engineers, while the 2015-17 batch has more than 13% students who are not engineers. At IIM Trichy, non-engineers consist of 24% of the batch for the first year and 7% for the final year. IIM Kozhikode has 10.5% non-engineers for the PGP batch admitted in 2016. Non-techies at IIM Ranchi have also gone up. While these were more than 11% of the 2014-16 PGP batch, this increased to 17% in the 2016-18 batch.

WHY PROMOTE DIVERSITY

According to Prof Anindya Sen, director in-charge, IIM Ranchi, "Engineers tend to think that there are always precise, mechanical solutions to all problems. However, management problems which usually have to do with human beings, need a more flexible approach. Moreover, male students sometimes lack in certain soft qualities which are essential for a harmonious workplace. Hence the need for diversification - with respect to both academic diversity and gender diversity." Citing an example of IIM Kozhikode, Prof Sony Thomas, chairperson (admissions), says, "The institute has been making deliberate efforts to ensure diversity in the classroom both academic and gender. We give 5% weightage to both non-engineering students as well as women candidates. However, a student will not get both. For example, a non-engineering woman applicant will get only 5% weightage. Similarly, a non-engineering male applicant will also get 5% weightage. Actually, it is a balancing act, since major proportion of female applicants are engineers too. For the PGP batch 2016, 89.5% are engineers and 26% are women."

IIM Ahmedabad endeavours to recognise exceptional performers in terms of their previous academic records, co-curricular and extra-curricular achievements, work experience, as well as their performance in CAT across diverse academic backgrounds. "In a discussion-based learning environment, such as that of IIM-A, diversity of participants' backgrounds and inclusivity of the institution's culture contribute significantly to a positive learning environment. Putting weight on the factors beyond performance in CAT helps the institute have a more diverse and inclusive student pool," says a spokesperson from the PGP admissions committee.

This need for diversity is also felt by the newer IIMs. As Prof Abhishek Totawar, chairperson placement and external relations, IIM Trichy, says, "Diversity, whether academic or gender, is important for management education. This is because most subjects are taught using the case study method, for which students from different academic backgrounds are preferred. Besides engineers who have a good background in quantitative analysis, we have non-engineers too with a strong command over quant."

Read the full story on www.hindustantimes.com/education

MORE NON-ENGINEERS JOINING INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT

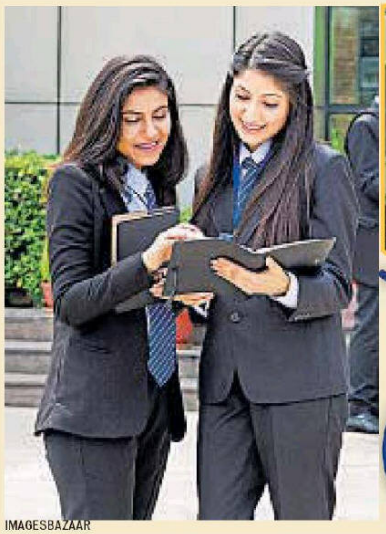

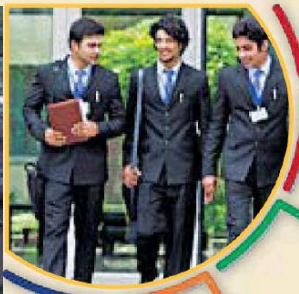

IMAGESBAZAAR

IIM AHMEDABAD
Non-engineering students in the PGP batch have gone up from 5% in 2011 to 20% this year

IIM BANGALORE
The 2016-18 batch includes 11% non-engineers, while the 2015-17 batch has more than 13% non-engineers

IIM RANCHI
While non-engineers were more than 11% of the 2014-16 PGP batch, this increased to 17% in the 2016-18 batch

IIM KOZHIKODE
IIM Kozhikode has 10.5% non-engineers for the PGP batch admitted in 2016

Gaya betel shopowner's IITian son makes his mark in US contest

http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx

Four years back when Anshuman, son of a betel shop owner Sunil Kumar cracked IIT , the newspapers sketched his struggle how he vaulted from a humble background to make it big. Four years after the big news, Anshuman has again become talk of town here. Anshuman, now a final year B Tech student of IIT Mumbai, has bagged second position in the 'Robo Sub', organised recently at Santiago city of the United States. The competition was attended by representatives of 11 countries, including the USA, Canada, China, Japan and Russia. Anshuman, who led a team of seven engineers, astonished the world with the latest prototype submarine design. Anshuman and his team were given the task at the competition to assemble an automatic submarine that was to be left in an open oceanic atmosphere. The submarine prototype was then required to identify the colour and touch the balloons. Out of the 11 countries, IIT Mumbai's model named 'Matasya'

stood second. Sunil Kumar, who barely knows the nitty gritty of his son Anshuman's achievement, is elated seeing the brouhaha round his house. A low profile man Sunil said, "Despite the fact that my financial condition is not so good, I have never turned deaf ears to the demands of my three sons and made them engineers. Anshuman is the second while his elder and youngest brothers are also engineers." He said, "When my son Anshuman informed me about his achievement in America, the entire Ganga Mahal, the residential society where we live, burst into joy and my wife organised a small puja." He admitted that he did not know much about the achievement of his son. "My neighbours and relatives term it as a big thing," he said. Talking to Hindustan Times from Mumbai, Anshuman said, "I am very happy with our scores at 'Robo Sub'. I dream to make my country self reliant in technology. The type of automatic submarine designed by us at IIT would help Indian Navy in many ways. It can reach places where humans cannot tread. It can be used as a multipurpose automatic submarine designed to compete with other war equipment under the water." Anshuman gave credit to his parents, brothers and school teachers for his achievement.

IIT KGPMIT join hands for course on urbanization

http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx

THE COURSE WILL START IN OCTOBER 2016. A JOINT REPORT WILL BE PRODUCED BY MIT AND IIT. FINAL PRESENTATION WILL BE MADE AT MIT

KOLKATA: The department of architecture and regional planning at IIT Kharagpur is joining hands with the School of Architecture and Planning, Massachusetts Institute of Technology (MIT), for a course in urbanisation in the developing world. The practical part of the course will be held at Santiniketan. The participants will study how planning can come up with practical norms, within a given ecological, regulatory, and investment terrain and climate. Under this course, a strategic plan will be prepared for environmental stewardship and watershed management of Bolpur's Khowai (canyons created by wind and water), including a technical model to portray the region. The practicum proposes a mutually enriching series of conversations and seminars between students of the two collaborating institutes. The group size will be 6–8 students from each institute. Primarily, graduate students, and few advanced undergraduate students will be enrolled for this course. The students would be divided into four groups working on the abovementioned research agendas. A group of faculty members and researchers across the MITHarvard Boston community and IIT Kharagpur would be guiding the discussions. Sessions will be held at MIT, IIT Kharagpur and Santiniketan, and conducted by means of videoconferencing. Use of a forum like Piazza, where all instructors and students could enroll for the course, will help in off class room participation and discussions. The course will start in October 2016. A joint report will be produced by MIT and IIT . Final presentation will be made at MIT during a two day colloquium in April 2017.

September 13

Hindustan Times ND 13.09.2016 P-23

Japanese firm awards scholarships to IIT students

HT ShineJobs Correspondent
yourviews@shine.com

■ **Scholarship winners from Indian Institutes of Technology with political leaders and representatives from Panasonic and Shine.com.**

To help meritorious undergraduate Indian Institute of Technology (IIT) students from economically weaker sections, Japanese firm Panasonic launched the second batch of its Ratti Chhatr Scholarship Programme this weekend.

The programme launched in partnership with India's second largest job portal Shine.com, was graced by chief guest Vijay Goel, minister for youth affairs and sports; Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog, government of India and Professor M Balakrishnan, deputy director (strategy and planning) IIT Delhi, who felicitated the awardees and their families.

Since its launch in India in 2009, Panasonic, in partnership with Shine.com, has been working to identify unexplored skills, particularly from the bottom of the pyramid and provide financial support to unleash their hidden talent. Till date, nine students have been selected and enrolled for the master's programme in Japan.

"It is admirable to see Panasonic India continuing its initiative of providing means of education to bright young talents across the country and helping them to achieve their ambitious goals," says Kant. "Ratti Chattr Scholarship is a progressive endeavour to create experts by providing financial assistance to young Indian students from economically weaker sections," says Manish Sharma, president and CEO, Panasonic India and South Asia, executive officer, Panasonic Corporation.

Tribune ND 13.09.2016 P-07

Govt to set up agency to fund research at IITs, IIMs

SEEMA KAUL
TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, SEPTEMBER 12

In a bid to boost innovation and build research-oriented infrastructure at premier institutions such as IITs and IIMs, an agency will soon be set up with government equity of ₹1,000 crore.

The HRD Ministry's proposal to this effect was today approved by the Union Cabinet, which also cleared the third phase of Technical Education Quality Improvement Programme (TEQIP) to enhance teaching-learning experience at educational institutions.

HRD Minister Prakash Javadekar said a Higher Education Financing Agency (HEFA) would be jointly promoted by an identified promoter and his ministry.

The HEFA would be formed as a Special Purpose Vehicle (SPV) with a PSU bank or a government-owned NBFC as promoter. It would also mobilise Corporate Social Responsibility (CSR) funds from PSUs and corporates, which would be released to promote research and innovation in these institutions on grant basis. The HRD Higher Education Secretary has been appointed as the Chairman of the Board of Governors of the SPV. HEFA will be run by the public sector bank within which it will be created. A decision in this regard will be taken within a month.

Prerequisites to join HEFA

- All centrally funded higher education institutes are eligible to be members of Higher Education Financing Agency (HEFA)
- The institution should agree to escrow a specific amount from their internal accruals to HEFA for a period of 10 years
- These secured funds from institutions will be used by HEFA to mobilise funds from the market. Each member institution is eligible for a credit limit to be decided by HEFA

All centrally funded higher education institutes are eligible to be HEFA members provided they agree to escrow a specific amount from their internal accruals to HEFA for 10 years. These secured funds from institutions will be used by HEFA to mobilise funds from the market. Each member institution is eligible for a credit limit to be decided by HEFA.

The HEFA will finance civil and lab infrastructure projects. The principal portion of the loan will be repaid through internal accruals (earned by institutes through fee receipts, research earnings etc).

"One third of the funds will be reserved for research infrastructure such as libraries and laboratories. There will be no increase in fee in any institute because of HEFA," Javadekar said.

The government announced ₹2,660 crore outlay for the third phase of TEQIP that involves equal contribution from Centre (₹1,330 crore) and World Bank (₹1,330 crore).

The focus states for TEQIP are Himachal, J&K, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, MP, UP, Rajasthan and eight Northeastern states and Andaman and Nicobar Islands. The project will be implemented with the facility of direct funds transfer to the accounts of beneficiary institutes. It will be initiated in the current year and will be co-terminus with Fourteenth Finance Commission (2019-20).

Business Standrad Hindi 13.09.2016 P-04

जीएसटी परिषद को हरी झंडी

बीएस संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 12 सितंबर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के गठन को मंजूरी दे दी। इस तरह से 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। नई कर व्यवस्था में जीएसटी परिषद को काफी ताकतवर बनाया गया है। गठन के बाद यह 22 नवंबर तक जीएसटी कर की दर, छूट पाने वाली वस्तुओं और जीएसटी लागू होने की कारोबार सीमा तय करने जैसे अहम मुद्दों पर फैसला करेगी।

परिषद की पहली बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 22-23 सितंबर को होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (राजस्व विभाग प्रभार), और राज्यों के वित्त मंत्री इसमें सदस्य होंगे। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव होंगे लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होगा।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज जीएसटी परिषद और इसका सचिवालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि सरकार जीएसटी लागू करने के मामले में समय के लिहाज से आगे चल रही है और 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की समयसीमा को लेकर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, 'अब यह जीएसटी परिषद पर निर्भर करता है कि वह दो महीने की तय समयसीमा के भीतर सभी मुद्दों पर विचार करे। हमने सभी प्रमुख आयामों पर चर्चा और अंतिम फैसले के लिए दो महीने की समयसीमा तय की है। यह व्यावहारिक होगी अथवा नही यह देखना होगा।'

उन्होंने कहा, '22 सितंबर से 22 नवंबर का समय प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।' सरकार जीएसटी कानून - केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) नवंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की योजना बना रही है।

अधिया ने कहा कि राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे जीएसटी परिषद में वित्त या कराधान या अन्य किसी मंत्री को नामित करें और उन्होंने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। अधिया ने कहा, 'अब तक हम तय समय से आगे चल रहे हैं। मुख्य चीज अब यह है कि जीएसटी परिषद की ज्यादा से ज्यादा बैठकें बुलाई जाए और सभी प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएग और उन्हें सुलझाया जाए ताकि हम कानून के मसौदे के साथ पूरी तरह तैयार हों और उद्योग अपने आपको तैयार कर सके।' जीएसटी परिषद में जहां केंद्र के पास एक तिहाई मत का अधिकार होगा वहीं राज्यों को इसमें दो तिहाई मत देने का अधिकार होगा। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए तीन चौथाई बहुमत जरूरी होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

- आईआईटी व आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी होगी, जो बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये तक उपलब्ध कराएगी
- कम आय वाले राज्यों, पर्वतीय राज्यों, अंडमान निकोबार के शिक्षा संस्थानों के मानकों में सुधार होगा
- मैंगनीज नाड्यूल उत्खनन के लिए इंटरनैशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ समझौते के विस्तार का फैसला
- एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) के तहत आयात शुल्क रियायत के आदान प्रदान को मंजूरी
- भारत-स्विट्जरलैंड के बीच 'अनियमित प्रवासियों' की वापसी पर समझौता मंजूर
- बीएसएफ के अधिकारियों के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी
- भारत-अफगानिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि होगी
- आवास एवं मानव बस्तियों पर समन्वय हेतु केन्या के साथ सहमति पत्र को मंजूरी

Hindustan ND 13.09.2016 P-16

आईएसएम धनबाद के सभी छात्रों को आईआईटी की डिग्री

नई दिल्ली। इसी साल आईआईटी का दर्जा हासिल करने वाले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आईएसएम) धनबाद के छात्रों को आईआईटी की डिग्री मिलेगी। केंद्र सरकार के नए कानून का फायदा संस्थान के चारों वर्ष के छात्रों को मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार, छह सितंबर को आईएसएम धनबाद को आईआईटी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे संबंधित विधेयक को पिछले दिनों संसद ने मंजूरी दी थी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार छह सितंबर 2016 के बाद दी जाने वाली सभी डिग्रियां आईआईटी के नाम की होंगी। दरअसल, इस साल जब इस संस्थान में दाखिले हुए थे तो वे आईएसएम के तौर पर हुए थे। लेकिन अब आधिकारिक रूप से यह आईआईटी बन चुका है। **(वि.सं.)**

India begins work on IIT-designed, climate-controlled border outpost near China border

The state-of-the-art border outpost will feature central heating, solar panels on roofs, recreation rooms and other modern amenities.

Indian government has begun construction of new climate-controlled border outposts in Ladakh for ITBP soldiers.

Indian soldiers posted on the high-altitude areas along the county's border with China can look forward to the first of its kind modern, eco-friendly and climate-controlled border outpost (BoP) for the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) in Ladakh.

"The work on the first BoP has started. It should be completed by May next year and our jawans can use it from next winter," the Times of India quoted an official as saying.

The state-of-the-art composite border outpost is said to feature central heating, solar panels on roofs, recreation rooms, toilets with hot water and other modern amenities like mess, armoury, medical room, office for senior officers and area for motor and animal transport. These BoPs are expected to house around 100 soldiers.

The construction of the first BoP has started in Lukung valley, at an expected cost of Rs. 17 crore.

These changes were brought in after Home Minister Rajnath SIngh's visit to a forward ITBP post last year. The home minister had promised additional funds for BoPs.

Soldiers posted in forward bases have to cope with harsh climate conditions, since the temperatures at these locations, which are at a height of over 15,000 feet, plunge to minus 45 degrees. However, these modern BoPs will keep temperatures in the range of 20-22 degree Celsius.

The government now plans 50 such BoPs at the cost of Rs. 700 to Rs. 800 crore. The designs for these outposts have been provided by IIT-Delhi and IIT-Roorkee.

Officials also revealed that once work is completed on the 50 BoPs, the government might take up work on 27 similar outposts in Arunachal Pradesh. ITBP soldiers posted in this region recently received SUVs like Toyota Fortuner and Mahindra Scorpio.